E-mail: justiceambit@gmail.com

E-mail: legalambit.ho@gmail.com

PRGI No: RJBIL/26/A2945

जस्टिस एम्बिट

नागौर से प्रकाशित...

हिन्दी एवं English समाचार पत्र

सत्य | न्याय | अधिकार

पढ़े.... 2

महिला सुरक्षा...

पढ़े.... 3

भाजपा देव ...

वर्षः 01 | डिजीटल अंक | नागौर, बुधवार 05 अगस्त, 2026 | मूल्यः 2.00 रुपए | पृष्ठः 4

हाईवे के दोनों तरफ 40 मीटर में अब निर्माण नहीं

रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने लैंड कन्वर्जन पर लगाई रोक; सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नोटिफिकेशन जारी

जयपुर। राजस्थान में नेशनल हाईवे पर अब 40 मीटर तक के एरिया में किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं मिलेगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सभी कलेक्टर को आदेश जारी करके अगले आदेशों तक ऐसे मामलों में जमीनों के कन्वर्जन पर रोक लगा दी। दरअसल कुछ महीने पहले फलोदी स्थित नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ था। इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने फरवरी 2026 को प्रदेश के सभी नेशनल हाईवे से नियमों के तहत 75 मीटर तक (हाईवे के मिड पॉइंट से) दूरी में बने सभी होटल, ढाबों का संचालन बंद करने और अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2026 में आदेश देते हुए 40 मीटर तक आवासीय और 75 मीटर तक कॉमर्शियल एक्टिविटी बंद करके नो-कंस्ट्रक्शन जोन बनाने के लिए कहा था। इसी आदेशों की पालना में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने हाल ही एक नोटिफिकेशन जारी करके नेशनल हाईवे के मिड पॉइंट से 40 मीटर की दूरी तक आ रही सभी जमीनों के लैंड यूज कन्वर्जन करने पर रोक लगा दी है।

75 मीटर तक कॉमर्शियल एक्टिविटी पर रोक

रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने 40 मीटर तक आवासीय और 75 मीटर तक कॉमर्शियल उपयोग के लिए जमीन के लैंड यूज पर रोक लगाई है। 40 मीटर के बाद केवल आवासीय निर्माण की अनुमति दी जा सकेगी। वहीं हाईवे के मिड पॉइंट से 75 मीटर तक कोई भी ढाबा, दुकान, रेस्टोरेंट, होटल, मोटल का संचालन नहीं होगा

हाईवे किनारे अवैध ढाबों और व्यवसायों पर सबसे बड़ी कार्रवाई

न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग के राइट ऑफ वे (**ROW**) के भीतर

किसी भी नए ढाबे, होटल या वाणिज्यिक निर्माण पर तत्काल रोक लगा दी है। सभी जिला मजिस्ट्रेटों को 60 दिन के भीतर मौजूदा अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। बिना **NHAI** की अनुमति कोई लाइसेंस, एनओसी या व्यापारिक स्वीकृति नहीं दी जा सकेगी।

भू-उपयोग बदलने पर भी सख्ती

राज्य सरकारों को आदेश दिया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य से 40 मीटर तक आवासीय और 75 मीटर तक वाणिज्यिक भूमि उपयोग परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी करें। इसका उद्देश्य भविष्य में सड़क किनारे अनियंत्रित व्यावसायिक विकास को रोकना है।

हर जिले में हाईवे सुरक्षा टास्क फोर्स

देश के प्रत्येक ऐसे जिले में, जहां से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, 15 दिन के भीतर जिला राजमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स गठित होगी। इसमें प्रशासन, पुलिस, **NHAI**, पीडब्ल्यूडी और स्थानीय निकायों के अधिकारी शामिल होंगे। हर 15 दिन में समीक्षा बैठक अनिवार्य होगी।

हर 75 किलोमीटर पर जीवनरक्षक व्यवस्था

अदालत ने माना कि दुर्घटना के बाद शुरुआती गोल्डन ऑवर में चिकित्सा सहायता नहीं मिलने से बड़ी संख्या में मौतें होती हैं। इसलिए प्रत्येक 75 किलोमीटर के भीतर बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, रिकवरी क्रेन और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं।

ट्रक चालकों को मिलेगा सुरक्षित विश्राम स्थल

देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर चरणबद्ध तरीके से ट्रक ले-बाय विकसित किए जाएंगे। इनमें सुरक्षित पार्किंग, विश्राम स्थल, भोजन, शौचालय, प्राथमिक उपचार और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था होगी।

ब्लैक स्पॉट छिपेंगे नहीं, सार्वजनिक होंगे

NHAI को 45 दिन में सभी दुर्घटना ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर सार्वजनिक सूची जारी करनी होगी। इन स्थानों पर हाई-मास्ट एलईडी, स्पीड कैमरे, चेतावनी संकेत और विशेष रोड मार्किंग अनिवार्य की गई है।

ड्रोन से निगरानी, जनता की शिकायत का अधिकार

राष्ट्रीय राजमार्गों की साल में कम से कम दो बार ड्रोन से निगरानी होगी। नागरिक 1033 हेल्पलाइन और राजमार्गयात्रा शिकायत पोर्टल पर जियो-टैग फोटो अपलोड कर अतिक्रमण या अवैध गतिविधियों की शिकायत कर सकेंगे। शिकायतों की ट्रैकिंग और अपील की व्यवस्था भी होगी। अपने आदेश में अदालत ने कहा कि जीवन का अधिकार केवल मृत्यु से सुरक्षा का अधिकार नहीं है, बल्कि राज्य का यह सकारात्मक दायित्व भी है कि वह नागरिकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराए।

राजस्थान में जमीन और घर खरीदना हुआ महंगा

4 महीने में दूसरी बार बढ़ी डीएलसी रेट; जयपुर के बापू बाजार में सबसे महंगी जमीन

जयपुर। राजस्थान में जमीन और मकान खरीदना महंगा हो गया है। सरकार ने सोमवार से पूरे राज्य में डीएलसी रेट बढ़ा दी हैं। इससे जमीनों की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी। साथ ही बाजार कीमत भी बढ़ेगी। डीएलसी रेट 5 से 49 फीसदी तक बढ़ाई गई हैं। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में 5 से 20 फीसदी तक दरें बढ़ाई गई हैं। वहीं, कुछ एरिया में डीएलसी रेट बहुत कम थीं, लेकिन ओपन मार्केट में जमीनों की दरें कई गुना ज्यादा थीं। वहां डीएलसी रेट में 30 से 49 फीसदी तक का इजाफा किया है। दरअसल, मई में सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों से जमीनों की नई डीएलसी रेट के प्रस्ताव मांगे थे। जून के आखिरी सप्ताह तक वित्त विभाग ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया। अब सरकार ने इन्हें 3 अगस्त से लागू कर दिया। इससे पहले एक अप्रैल 2026 को डीएलसी रेट में 10% की बढ़ोतरी की थी।

गहलोत बोले- भाजपा विधायक जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं

विधायक रेवतराम डांगा पहले स्टिंग में पकड़े गए थे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया

जोधपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के एकजुटता होने और निकाय एवं पंचायत चुनाव में जीत का दावा किया। जोधपुर में बोलते हुए कई मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने सरकार के मंत्रियों और विधायकों पर कटाक्ष किया। गहलोत ने कहा- खींवसर (नागौर) विधायक रेवतराम डांगा पहले स्टिंग में पकड़े गए थे लेकिन कोई जवाब नहीं आया। डांगा ने 205 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया। वहीं केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने सब्सिड़ी के 90 लाख रुपए उठा लिए। संसद में मुद्दा बनने पर वापस जमा करवाया। गहलोत ने कहा कि जमा कराने से क्राइम खत्म नहीं होता। उदयपुर के विधायकों पर भी आरोप है कि वे आदिवासी परिवारों को बंधक बनाकर जमीन कब्जा रहे हैं। गहलोत ने स्वास्थ्य सेवाओं, कानून-व्यवस्था,प्रशासनिक कार्यशैली,आदिवासी क्षेत्रों की स्थिति,अरावली संरक्षण,मानगढ़ धाम सहित कई विषयों पर अपनी बात रखी।

महिपाल मकराना बोले- मांगें नहीं मानी तो सीएम हाउस घेरेंगे

प्रदर्शन में घायल कार्यकर्ता की मौत के बाद परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी मांगी

जयपुर। श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने मंगलवार को यूजीसी रोल बैक की मांग को लेकर जयपुर में हुए आंदोलन के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया- संगठन शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहा था। लेकिन प्रशासन ने तय सहमति के बावजूद एक किलोमीटर आगे बढ़ते ही प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन और लाठीचार्ज कर दिया। मकराना ने पुलिस प्रशासन, राज्य सरकार और विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कई मांगें रखीं। साथ ही 7 दिन में मांगें नहीं मानने पर सीएम हाउस का घेराव करने की चेतावनी दी। महिपाल सिंह मकराना ने बताया- करणी सेना ने 24 दिनों में 50 से 60 कस्बों से होकर करीब 800 किलोमीटर की पदयात्रा की। गांव-गांव जाकर यूजीसी के मुद्दे पर लोगों को जागरूक किया। जयपुर पहुंचने से पहले कई दिनों से प्रशासन के साथ लगातार बातचीत चल रही थी। प्रशासन शहर के बाहर ही ज्ञापन लेने की बात कह रहा था, लेकिन संगठन ने कलेक्टर को ही ज्ञापन सौंपने की मांग रखी थी। मकराना ने आरोप लगाया- प्रशासन ने हमें पानीपेच चौराहे तक जाने की अनुमति दी थी, लेकिन कालवाड़ पुलिया के नीचे पहुंचते ही बिना किसी चेतावनी के प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन चला दिया गया। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों पर भी लाठियां बरसाई गईं। आंदोलन पूरी तरह गांधीवादी तरीके से किया जा रहा था। उनके मुताबिक प्रदर्शनकारी हाथों में गीता और संविधान लेकर चल रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि वाटर कैनन की चपेट में आने से देवराज

सिंह पलाड़ा घायल हुआ। घर पहुंचने के बाद उसने सीने में दर्द की शिकायत की। पहले घरवाले अंबे अस्पताल ले गए, वहां से एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया। लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। देवराज सिंह रावणा राजपूत समाज से थे। ओबीसी वर्ग से आते थे।

पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी देने की मांग

मकराना ने कहा- संगठन की मांग है कि वाटर कैनन चलाने और कार्रवाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। एडिशनल एसपी बजरंग सिंह, डीवाईएसपी बी.एल. मीणा और एसएचओ गुरु भूपेंद्र को निलंबित करने की मांग की। साथ ही मृतक देवराज सिंह के परिवार को एक करोड़ रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देने की मांग भी रखी। उन्होंने चेतावनी दी कि सात दिन के अंदर सरकार वार्ता नहीं करती। जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती तो करणी सेना सीएम हाउस का घेराव करेगी। राजस्थान बंद का आह्वान करेगी। नगर निगम चुनाव में भी संगठन घर-घर जाकर लोगों को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देगा। भाजपा के खिलाफ मतदान की अपील करेगा।

सरकार औ विपक्ष दोनों पर सवाल उठाए

महिपाल सिंह मकराना ने सरकार के साथ-साथ विपक्ष पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान न तो सत्ता पक्ष का कोई बड़ा नेता मिलने आया और न ही विपक्ष ने आवाज उठाई। मकराना ने कहा - बीजेपी का तो समझ में आता है। लेकिन इस रैली में कांग्रेस का भी कोई नेता प्रदर्शनकारियों से मिलने नहीं पहुंचा। मकराना ने यह भी कहा कि आंदोलन में केवल सवर्ण समाज ही नहीं, बल्कि ओबीसी वर्ग के लोग भी साथ थे। प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने सरकार और मंत्रियों के सामने आंदोलनकारियों की गलत छवि पेश की, जिसके कारण शांतिपूर्ण पदयात्रा के साथ ऐसा व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि करणी सेना की मांग तब तक जारी रहेगी, जब तक यूजीसी रोल बैक नहीं होता। सरकार वार्ता नहीं करती और पुलिस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की जाती।

अन्य राज्यों में भी पैदल यात्राएं निकालेंगे

महिपाल सिंह मकराना ने कहा- यदि निर्धारित समय सीमा में सरकार इन मांगों को स्वीकार नहीं करती है तो आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार दिया जाएगा। इसके तहत राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों में एक साथ पैदल यात्राएं निकाली जाएंगी। इसके बाद दिल्ली का घेराव कर सरकार के समक्ष अपनी मांगों को मजबूती से रखा जाएगा।

हाईकोर्ट बोला-ट्रिब्यूनल चला नहीं सकते तो बंद कर दो

सरकार 7 दिन में रेट में अध्यक्ष-सदस्य नियुक्त करे; इतने ट्रांसफर कर दिए, कर्मचारी कहां जाएंगे

जयपुर। हाईकोर्ट ने राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण (रेट) में अध्यक्ष और सदस्यों के खाली पदों को लेकर राज्य सरकार पर नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा- अगर ट्रिब्यूनल नहीं चला सकते हो तो इसको बंद कर दो। अदालत ने कहा कि आपने इतनी बड़ी तादाद में ट्रांसफर कर दिए, कर्मचारी अपनी शिकायत लेकर कहां जाएंगे। यह टिप्पणी जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने वकील दिलीप सिंह कुरका, संदीप कलवानिया सहित अन्य वकीलों की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए की। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि 7 दिन में रेट में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करें। अगर नियुक्ति नहीं होती है तो 11 अगस्त को कार्मिक सचिव हाईकोर्ट में पेश हो जाएं।

4 महीने से चेयरमैन का पद खाली

रेट चेयरमैन के रूप में विकास सीताराम भले का 19 मार्च 2026 को ट्रांसफर होने के बाद से यह पद खाली चल रहा है। इसके अलावा रेट में चार सदस्यों के पद भी हैं। इसमें से दो पद लंबे समय से खाली चल रहे हैं। एक सदस्य के पद पर पूर्व **IAS** अधिकारी प्रकाश शर्मा को अध्यक्ष का कार्यभार दे रखा है। वहीं न्यायिक सदस्य पूनम दरगन बीमारी के कारण रेगुलर नहीं हैं।

डोटासरा बोले- सरकार की नाकामी के कारण हाईकोर्ट को आदेश देना प?ा

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा- आखिर.. हाईकोर्ट को भाजपा सरकार की नाकामी के कारण राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण (रेट) में अध्यक्ष और सदस्यों की 7 दिन में नियुक्ति करने का आदेश देना ही पड़ा। ये आदेश बताता है कि भाजपा सरकार में लापरवाही और प्रशासनिक विफलता का आलम क्या है। डोटासरा ने लिखा- यही सवाल हमने कुछ दिन पहले उठाया था.. आखिर न्याय की उम्मीद में बैठे कर्मचारी जाएं तो कहां जाएं? क्योंकि भाजपा सरकार पहले कर्मचारियों के मनमाने तबादले करती है, फिर जिस अधिकरण (ट्रिब्यूनल) में कर्मचारी न्याय मांगने जाएं।

मोबाइल में सेव डेटा बन सकता साइबर ठगी का कारण

पासवर्ड-बैंकिंग डिटेल-निजी डॉक्यूमेंट रखना पड़ सकता भारी; रोज होते 1.3 लाख से ज्यादा साइबर हमले

जयपुर। स्मार्टफोन में बैंकिंग, डिजिटल लॉकर और निजी डॉक्यूमेंट रखने से साइबर ठगों का शिकार बन सकते हैं। ऐसे में मोबाइल में संवेदनशील जानकारी सेव रखना खतरा पैदा कर सकता है। यह देखते हुए राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की। महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर जारी एडवाइजरी में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (साइबर क्राइम) वीके सिंह ने बताया- भारत में प्रतिदिन 1.3 लाख से अधिक साइबर हमले होते हैं। ऐसे में मोबाइल में सेव निजी जानकारी, बैंकिंग डिटेल और डॉक्यूमेंट साइबर ठगी, पहचान चोरी और आर्थिक नुकसान का कारण बन सकते हैं।

बैंक ऑफ बड़ौदा में कस्टमर के डेटा लीक से लिया सबक

राजस्थान पुलिस ने हाल ही सामने आए बैंक ऑफ बड़ौदा में कस्टमर के डेटा लीक और डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों का हवाला दिया। वीके सिंह ने बताया- एक कर्मचारी के ईमेल से करीब 1 टीबी डेटा डार्क वेब पर लीक होने का मामला सामने आया था। यह घटना बताती है कि डिजिटल सुरक्षा में छोटी सी चूक भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है।

साइबर ठगी होने पर तुरंत करें शिकायत

राजस्थान पुलिस ने कहा- यदि किसी भी प्रकार की साइबर ठगी या संदिग्ध गतिविधि का सामना हो तो तुरंत पास के पुलिस थाना या साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत करें।

सोशल मीडिया रील और स्टंटबाजी के नाम पर डर फैलाने वालों पर चौरासी पुलिस का शिकंजा : 12 पावर बाइक्स की जब्त

संतोष व्यास@जस्टिस एम्बिट

डूंगरपुर। सड़कों पर तेज रफ्तार से बाइक चलाकर और स्टंटबाजी के जरिए आमजन में खौफ पैदा करने वाले हुड़दंगियों के खिलाफ पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत चौरासी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 पावर बाइक्स को डिटेन किया है। एसपी के निर्देशानुसार चौरासी थानाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। इस टीम ने अलग-अलग समूह बनाकर सड़कों पर बेधड़क तेज गति से पावर बाइक दौड़ाने और दहशत फैलाने वालों पर नकेल कसते हुए यह कार्रवाई की।

स्टंटबाजी और रील बनाने वालों को पुलिस की चेतावनी

जिला पुलिस अधीक्षक ने आमजन और युवाओं से अपील की है कि वे अलग-अलग नामों से ग्रुप बनाकर स?कों पर भय का माहौल न बनाएं। रील बनाने या सोशल मीडिया पर वाहवाही लूटने के लिए गाड़ियों के साथ जानलेवा स्टंट न करें, इससे खुद की और दूसरों की जान जोखिम में पड़ती है। उन्होंने कहा कि स्टंट और हथियारों के साथ फोटो या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा सोशल मीडिया हैंडल पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे किसी ग्रुप या स्टंट करने वालों के बारे में जानकारी देना चाहता है, तो वह डूंगरपुर पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर सूचित कर सकता है।

पादरा गांव की सड़कें बनीं दलदल, ग्रामीणों का पैदल और वाहनों से आवागमन हुआ बेहद जोखिम भरा

अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की अनदेखी से ग्रामीणों में भारी आक्रोश

संतोष व्यास@जस्टिस एम्बिट

डूंगरपुर। जिले के सागवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत पादरा में मानसून की बारिश ने स्थानीय व्यवस्थाओं और बदहाल बुनियादी ढांचे की पोल खोलकर रख दी है। लगातार हो रही बारिश के कारण गांव के प्रमुख संपर्क मार्ग और आंतरिक सड़कें पूरी तरह दलदल में तब्दील हो चुकी हैं। जगह-जगह बने गहरे गड्ढों और जलभराव के चलते ग्रामीणों का पैदल चलना और वाहनों से गुजरना अत्यंत जोखिम भरा हो गया है, जिससे पूरे गांव में आवागमन की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि पादरा गांव की सड़कें पिछले लंबे समय से जर्जर स्थिति में थीं। मानसून के आगमन के साथ ही जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने से स्थिति और अधिक भयावह हो गई है। सड़कों पर जमा कीचड़ के कारण आए दिन दोपहिया वाहन चालक फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। इस स्थिति से सबसे अधिक प्रभावित स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे, किसान, महिलाएं और बुजुर्ग हो रहे हैं, जिन्हें अपने दैनिक कार्यों के लिए जान जोखिम में डालकर इन रास्तों से गुजरना पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि जर्जर सड़कों की समस्या को लेकर कई बार संबंधित विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर स्थिति से अवगत कराया गया, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही हाथ लगा। किसी भी स्तर पर कोई ठोस और स्थायी कार्रवाई न होने का नतीजा आज पूरा गांव भुगत रहा है। गांव में बढ़ते जनाक्रोश के बीच ग्रामीणों ने एक बार फिर जिला प्रशासन और ग्राम पंचायत से गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने मांग की है कि समस्या की गंभीरता को देखते हुए क्षतिग्रस्त रास्तों की तत्काल प्रभाव से मरम्मत कराई जाए तथा पानी की निकासी के लिए स्थायी व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य में बारिश के दौरान लोगों को इस प्रकार की नारकीय स्थिति का सामना न करना पड़े।

डाबर के 100% शुद्ध दावे वाले प्रोडक्ट पर रोक

FSSAI ने शहद-घी समेत कई सामान बेचना बैन किया; 15 दिन में रिपोर्ट मांगी

नई दिल्ली। डॉबर के कई प्रोडक्ट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इनमें शहद और गाय का घी भी शामिल है। ये प्रोडक्ट 100% शुद्धता के दावे के साथ बेचे जा रहे थे। यह रोक खाने-पीने के सामानों के मानक तय करने वाली सरकारी संस्था FSSAI ने लगाई है। फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इन दावों को गुमराह करने वाला बताया है। इस पर डाबर से 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है। सोमवार 3 अगस्त को FSSAI ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी है। FSSAI के अनुसार, कंपनी की वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य पदार्थों पर भ्रामक दावे पाए गए थे। इनमें 100% नेचुरल, 100% प्योर, 100% प्योरिटी गारंटेड, 100% ऑर्गनिक और 100% टेंडर कोकोनट वॉटर जैसे लेबल शामिल थे। FSSAI का कहना है कि 100 प्रतिशत दावों का यह उपयोग FSS विनियम, 2018 का उल्लंघन करता है। ये दावे अस्पष्ट, असत्यापित और उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले हैं।

सीएचओ संघ ब्लॉक दोवड़ा की कार्यकारिणी घोषित, राजकुमार कटारा बने ब्लॉक अध्यक्ष

संतोष व्यास@जस्टिस एम्बिट

डूंगरपुर। जिले के दोवड़ा ब्लॉक में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक मंगलवार को आयोजित की गई, जिसमें संगठन की मजबूती और सीएचओ के हितों की रक्षा के उद्देश्य से सर्वसम्मति से नई ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से राजकुमार कटारा को दोवड़ा ब्लॉक अध्यक्ष चुना गया। नवगठित कार्यकारिणी में नीलम जोशी को उपाध्यक्ष, निलेश रोत को सचिव तथा अशोक कुमार मीणा को कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा, संगठन की गतिविधियों को गति देने के लिए अंकित पंड्या, हिना अहारी, मनीष परमार, सुरेश खराड़ी, अरविंद पाटीदार एवं अक्षयराज सिंह चुण्डावत को कार्यकारिणी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

सेवा संबंधी समस्याओं और संगठन की एकजुटता पर मंथन

बैठक के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के सामने आ रही सेवा संबंधी व्यावहारिक समस्याओं के समाधान, कैडर के हितों के संरक्षण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को ओर अधिक प्रभावी एवं सुलभ बनाने जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। वक्ताओं ने कहा कि एक मजबूत और संगठित ढांचा ही अधिकारियों की समस्याओं को उचित मंच तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा।

एकजुटता और जनसेवा के संकल्प के साथ हुआ बैठक का समापन

बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने नवगठित कार्यकारिणी का ढोल-धमाकों और उत्साह के साथ स्वागत किया तथा विश्वास जताया कि नई टीम संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। कार्यक्रम का सफल संचालन अंकित पंड्या द्वारा किया गया, जबकि बैठक के अंत में मनीष परमार ने सभी उपस्थित अधिकारियों का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। बैठक का समापन संगठन की एकजुटता, आपसी सहयोग और आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के संकल्प के साथ हुआ।

महिला सुरक्षा सलाह केंद्र एवं सखी सेंटर द्वारा साथिनों की बैठक आयोजित

ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को जागरूक करने और पोक्सो व घरेलू हिंसा कानून की जानकारी देने पर दिया गया जोर

संतोष व्यास@जस्टिस एम्बिट

डूंगरपुर। महिला सुरक्षा सलाह केंद्र, सखी वन स्टॉप सेंटर और पीएसएसके की कार्यकर्ताओं द्वारा मंगलवार को साथिनों की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में उपस्थित साथिनों को महिला सुरक्षा एवं कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं, कानूनी प्रावधानों और सहायता प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने महिला सुरक्षा सलाह केंद्र की कार्य प्रणाली और इसके मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए लागू पोक्सो एक्ट, दहेज निषेध अधिनियम और घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के कानूनी पहलुओं से सभी को अवगत कराया गया। साथ ही महिला अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी साझा की गई। उपस्थित अधिकारियों ने साथिनों को प्रेरित करते हुए निर्देश दिए कि वे ग्राम स्तर पर

महिलाओं के साथ नियमित बैठकें आयोजित करें। इन बैठकों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर जागरूक किया जाए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया गया कि यदि गांव में कोई भी पीड़ति या परेशान महिला मदद के लिए पहुंचती है, तो उसे तत्काल सखी सेंटर अथवा महिला सुरक्षा सलाह केंद्र के माध्यम से त्वरित सहायता और सहयोग प्रदान करने की प्रक्रिया से जोड़ा जाए। इस अवसर पर सुपरवाइजर सुचिता कलाल सहित विभाग का समस्त स्टाफ और बड़ी संख्या में साथिनें मौजूद रहीं।

रिपोर्ट- ईरानी सुप्रीम लीडर ने राष्ट्रपति पजशकियान को चेताया

सेना के हिसाब से चलेगी सरकार; सुरक्षा मुद्दों पर कमांडर वाहिदी को आखिरी फैसले का अधिकार

नई दिल्ली। ईरान में राष्ट्रपति मसूद पजशकियान और टॉप लीडरशिप के बीच मतभेद की खबरें सामने आई हैं। इजराइली चैनल-14 की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई ने राष्ट्रपति से साफ कह दिया है कि सरकार अब सेना के हिसाब से चलेगी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, अमेरिका से बातचीत और परमाणु कार्यक्रम जैसे अहम मामलों में अब IRGC कमांडर अहमद वाहिदी का फैसला अंतिम माना जाएगा। यानी इन मुद्दों पर राष्ट्रपति की भूमिका पहले से काफी सीमित हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, पजशकियान पहले भी कई बार इस्तीफा देने की पेशकश कर चुके हैं। उनका कहना था कि उनकी सरकार को बड़े फैसलों से दूर रखा जा रहा है। अब खामेनेई ने कथित तौर पर साफ कर दिया है कि सरकार की नीति सेना की रणनीति के मुताबिक ही चलेगी।

अमेरिका-ईरान वार्ता की तारीख और जगह अब तक तय नहीं

अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित बातचीत को लेकर अभी तक तारीख और स्थान तय नहीं हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान और कतर संभावित मेजबान देशों के तौर पर चर्चा में हैं और दोनों देश मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं।

ईरान की नई रणनीति- जंग नहीं, अमेरिका पर दबाव बढ़ाना

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान अब सीधी सैन्य जीत के बजाय समुद्री व्यापार, तेल आपूर्ति और अहम शिपिंग रूट्स पर दबाव बनाकर अमेरिका और उसके सहयोगियों की लागत बढ़ाने की रणनीति अपना रहा है।

ईरान का दावा- होर्मुज के ऊपर उड़ रहा रीपर ड्रोन मार गिराया

IRGC ने दावा किया कि उसने होर्मुज स्ट्रेट के ऊपर उड़ रहे स्क्-9 रीपर ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया। हालांकि, यह नहीं बताया गया कि ड्रोन किस देश का था।

अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ाने के नए विकल्प तलाश रहा

CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अपने सैन्य विश्लेषकों से ईरान पर दबाव बढ़ाने और उसे सजा देने के लिए नए सुझाव मांगे हैं। अधिकारियों ने इसे असामान्य कदम बताया है। 5. हूती धमकी के बाद 6 सऊदी सुपरटैंकरों ने रास्ता बदला- यमन के हूती विद्रोहियों की धमकी के बाद छह सऊदी सुपरटैंकरों ने लाल सागर और बाब-अल-मंदेब के बजाय अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से से लंबा समुद्री रास्ता अपनाया। इससे क्षेत्र में शिपिंग सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई।

प्रशासनिक उपेक्षा की मार झेल रहा ग्राम पंचायत दिवडा बडा : नालियाँ चोक, सडकों पर फैला बदबूदार पानी

स्कूली बच्चे गंदे पानी से होकर जाने को मजबूर, बीमारियों के फैलने का खतरा बडा, ग्रामीणों में आक्रोश

संतोष व्यास@जस्टिस एम्बिट

डूंगरपुर। पंचायत प्रशासन की अकर्मण्यता और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी का खामियाजा आज आम जनता को भुगतना पड रहा है। जिले के ब्लॉक गलियाकोट की ग्राम पंचायत दिवडा बडा में साड-सडाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। गाँव की नालियों की लंबे समय से सडाई न होने के कारण वे पूरी तरह चोक हो चुकी हैं, जिससे नालियों का बदबूदार और दूषित पानी ओवरफ्लो होकर मुख्य सडकों पर जमा हो रहा है।

स्कूली बच्चों और राहगीरों के लिए बनी आफत

सडक पर हो रहे जलभराव और कीचड के कारण सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले छोटे-छोटे नौनिहालों को उठानी पड रही है। बच्चे रोडाना इसी गंदे पानी से होकर स्कूल जाने को मजबूर हैं, जिससे न केवल उनकी ड्रेस और जूते गंदे हो रहे हैं, बल्कि फिसलकर चोटिल होने का जोखिम भी लगातार बना हुआ है। इसके अलावा, राहगीरों और वाहन चालकों के

लिए भी इस मार्ग से निकलना दूभर हो गया है।

बीमारी और महामारी का सता रहा डर

स्थानीय निवासियों का कहना है कि सडकों पर जमा गंदे पानी से लगातार तीव्र दुर्गंध उठ रही है। पानी के ठहराव के कारण मच्छरों का प्रकोप अत्यधिक बड गया है, जिससे डेंगू, मलेरिया जैसी संक्रामक बीमारियाँ फैलने की भयंकर आशंका बनी हुई है। ग्रामीण अपने और अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित हैं।

केवल आश्वासन, धरातल पर कोई काम नहीं

समाजसेवी संतोष पाटीदार व अन्य ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई बार इस समस्या से ग्राम पंचायत प्रशासन और प्रतिनिधियों को अवगत कराया। लेकिन हर बार उन्हें केवल खोखले आश्वासन ही नसीब हुए हैं। जमीनी स्तर पर स्थिति जस की तस बनी हुई है और जिम्मेदार अधिकारी आँखें मूँदे बैठे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द नालियों की सडाई करवाकर जलभराव की समस्या से निजात नहीं दिलाई गई, तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।

आयुर्वेद विभाग में सेवानिवृत्त कर्मियों की पुनर्नियुक्ति का विरोध : युवाओं ने उठाई नियमित भर्ती की मांग

मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपकर 926 रिक्त पदों पर पारदर्शी एवं आरपीएससी के जरिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का किया आग्रह

संतोष व्यास@जस्टिस एम्बिट

डूंगरपुर। आयुर्वेद विभाग में सेवानिवृत्त चिकित्साकर्मियों की पुनर्नियुक्ति के प्रस्ताव को लेकर प्रदेश के आयुर्वेद स्नातकों, स्नातकोत्तर युवाओं और प्रतियोगी अभ्यर्थियों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। इस फैसले के विरोध में समस्त आयुर्वेद युवा संघ के तत्वावधान में युवाओं ने मंगलवार को डूंगरपुर जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए सेवानिवृत्त कर्मियों की पुनर्नियुक्ति प्रक्रिया को तत्काल निरस्त करने और राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के माध्यम से पारदर्शी एवं नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई है।

926 पदों में से 899 पद पदोन्नति के लिए रिक्त

ज्ञापन में बताया गया है कि प्रदेश के आयुर्वेद विभाग में वर्तमान में लगभग 926 पद रिक्त पड़े हैं, जिनमें से लगभग 899 पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने हैं।

हालांकि, विभिन्न संवर्गों में पिछले कई वर्षों से डीपीसी प्रक्रिया लंबित पड़ी है। इसके चलते लगभग 310 चिकित्साधिकारी विभिन्न आयुर्वेद महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में कार्यव्यवस्था के तहत कार्यरत हैं। युवाओं ने आरोप लगाया कि नियमित नियुक्ति के स्थान पर सरकार द्वारा कार्यव्यवस्था, प्रतिनियुक्ति या यूटीबी जैसी अस्थायी व्यवस्थाओं से काम चलाया जा रहा है, जो राज्य के योग्य युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।

संविधान के अनुच्छेदों का दिया हवाला

आयुर्वेद युवा संघ के प्रतिनिधि डॉ. कुशराज सिंह सिसोदिया ने बताया कि आरपीएसी के माध्यम से लंबे समय से आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों की नियमित भर्ती आयोजित नहीं की गई है, जिससे प्रदेश के हजारों युवाओं के रोजगार के अवसर प्रभावित हो रहे हैं। ज्ञापन में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 का संदर्भ देते हुए मांग की गई है कि पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक और विधिसम्मत होनी चाहिए। ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधिमंडल में डॉ. कुशराज सिंह सिसोदिया, डॉ. धर्मेन्द्र पाल सिंह, डॉ. दुष्यंत कटारा तथा डॉ. विनय डेंडोर सहित कई आयुर्वेद चिकित्सक व अभ्यर्थी शामिल रहे। युवाओं ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी जायज मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो वे राज्यव्यापी आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

तमिलनाडु के नेता विपक्ष उदयनिधि स्टालिन पर केस

चेन्नइ। तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ अभिनेत्री तृषा पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मामला दर्ज किया गया है। मंगलवार को पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस ने छह धाराओं में केस दर्ज किया है। वहीं, गिरफ्तारी से बचने के लिए उदयनिधि ने मद्रास हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की है। सोमवार को तंजावुर में कावेरी जल विवाद पर आयोजित रैली में उदयनिधि मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय पर निशाना साध रहे थे। इसी दौरान भीड़ से तृषा, तृषा के नारे लगे। आरोप है कि इस पर उन्होंने कहा, पानी कहीं और पहुंचे या न पहुंचे, वहां जरूर पहुंचना चाहिए। बाद में उन्होंने सफाई दी कि उनका इशारा कावेरी के पानी की ओर था।

कई पार्टियों ने भी आलोचना की थी

टीवीके विधायक रेवंत चरण ने कहा कि इससे डीएमके की राजनीतिक संस्कृति और सोच उजागर होती है। टीवीके नेता आधव अर्जुन ने उदयनिधि को अश्लील निधि बताते हुए कहा कि उन्होंने राजनीतिक संवाद का स्तर गिराया है। तमिलनाडु भाजपा के मुख्य प्रवक्ता नारायणन तिरुपति ने टिप्पणी को अश्लील और शर्मनाक बताते हुए उदयनिधि की गिरफ्तारी की मांग की। भाजपा नेता खुशबू सुंदर ने कहा कि उन्हें अभिनेत्री तृषा से बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए।

DMK की सफाई- उदयनिधि ने किसी का नाम नहीं लिया

डीएमके सांसद टी.आर. बालू ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उदयनिधि ने किसी महिला का नाम नहीं लिया और पूरा विवाद झूठा है। वहीं, पूर्व मंत्री टी. मनो थंगराज ने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा कि कावेरी मुद्दे और डेल्टा क्षेत्र के किसानों की समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए इस विवाद को हवा दी जा रही है।

तृषा और विजय के रिश्ते की चर्चाएं

तृषा कृष्णन और विजय पिछले दो दशक से तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चर्चित ऑन-स्क्रीन जोड़ों में रहे हैं।

भाजपा देवसोमनाथ मंडल बैठक में संगठन की एकजुटता पर बल, पंचायती राज चुनाव की तैयारियों को लेकर हुआ मंथन

संतोष व्यास@जस्टिस एम्बिट

डूंगरपुर। भारतीय जनता पार्टी देवसोमनाथ मंडल की मासिक बैठक देवसोमनाथ मंदिर परिसर में मंडल अध्यक्ष किरण पंड्या की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न हुई। प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार आयोजित इस बैठक में आगामी पंचायती राज चुनाव की रणनीतियों, बूथ स्तर तक संगठन को सुदृढ़ करने तथा संगठनात्मक एकजुटता पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि जिला उपाध्यक्ष धनेश्वर अहारी एवं जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष भंवरलाल कटारा उपस्थित रहे।

व्यक्तिगत मतभेद भुलाकर एकजुटता का आह्वान

बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि किसी भी चुनाव में सफलता का मुख्य आधार मजबूत संगठन और अनुशासित कार्यकर्ता होते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को दरकिनार कर संगठन हित में एकजुट होकर कार्य करने की अपील की। वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि आगामी पंचायती राज चुनाव की चयन प्रक्रिया में योग्य, शिक्षित, कर्मठ, ईमानदार और सेवाभावी कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की रही मौजूदगी

बैठक के दौरान संगठन को बूथ स्तर तक अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर मंडल सह प्रभारी बहादुर पाटीदार, पूर्व मंडल अध्यक्ष मनसुख पाटीदार, वरिष्ठ नेता प्रेमनाथ पाटीदार, मंडल उपाध्यक्ष अर्जुन दास, वल्लभ पाटीदार, मंडल मंत्री हीरालाल खराड़ी, शंकरलाल कलाल, जितेंद्र सिंह चारण, देवीलाल, रामलाल अहारी, कान्तिलाल परमार, महेंद्र पाटीदार सहित मंडल के अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन मंडल महामंत्री विरमल परमार ने किया, जबकि बैठक के अंत में मंडल उपाध्यक्ष अशोक सेवक ने उपस्थित सभी अतिथियों व कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया।

कांकरादरा में 30 लाख की लागत से बनी सीसी सड़क का विधायक घोगरा ने किया लोकार्पण, ग्रामीणों को आवागमन की समस्या से मिलेगी मुक्ति

संतोष व्यास@जस्टिस एम्बिट

डूंगरपुर। क्षेत्रीय विकास की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा ने मंगलवार को ग्राम पंचायत कांकरादरा में स्थानीय विधायक विकास मद से निर्मित नव-निर्मित सीसी सड़क का फीता काटकर एवं पट्टिका का अनावरण कर विधिवत लोकार्पण किया। कुल 30 लाख रुपये की लागत से तैयार हुई इस आधुनिक सड़क से क्षेत्र के ग्रामीणों को लंबे समय से चली आ रही कीचड़ और उबड़-खाबड़ रास्तों की समस्या से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए विधायक गणेश घोगरा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कांकरादरा और आसपास के गांवों में सडकों के सुदृीकरण से न केवल आवागमन सुलभ होगा, बल्कि स्थानीय व्यापार और जनजीवन को भी नई गति मिलेगी।

कांकरादरा व चक महुडी के ग्रामीणों में उत्साह

समारोह के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने विधायक गणेश घोघरा का भव्य स्वागत किया। लोकार्पण कार्यक्रम में कांकरादरा और चक महुडी ग्राम पंचायतों से बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे।

ग्रामीणों ने 30 लाख की लागत से बनी इस गुणवत्तापूर्ण सड़क के निर्माण के लिए विधायक का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस मार्ग के बनने से बारिश के मौसम में होने वाली भारी दिक्कतों से हमेशा के लिए राहत मिल गई है। कार्यक्रम का समापन ग्रामीणों के उत्साहवर्धन और विकास कार्यों को निरंतर जारी रखने के संकल्प के साथ हुआ।

रेटा विद्यालय में इकलौते शिक्षक की प्रतिनियुक्ति निरस्त करने की मांग, ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन

ग्रामीणों का आरोप : अंग्रेजी शिक्षक की तहसील कार्यालय में प्रतिनियुक्ति से प्रभावित हो रही बच्चों की पढ़ाई

संतोष व्यास@जस्टिस एम्बिट

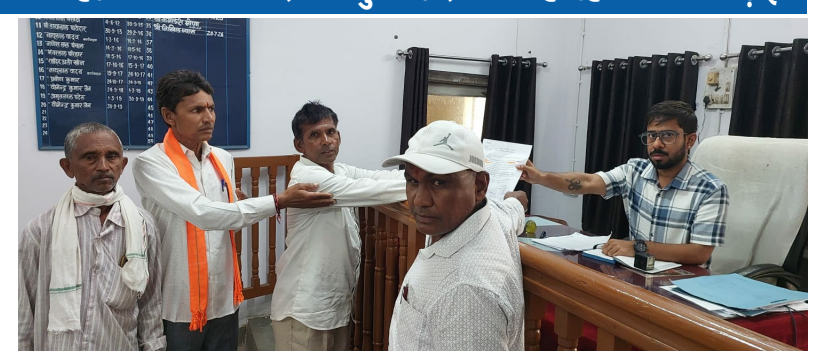

डूंगरपुर। जिले के ग्राम पंचायत रेटा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत करीब 300 विद्यार्थियों की पढ़ाई पर मंडरा रहे संकट को देखते हुए ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। विद्यालय में पदस्थापित अंग्रेजी विषय के एकमात्र शिक्षक शादाब हुसैन की तहसील कार्यालय में लगाई गई प्रतिनियुक्ति को तत्काल निरस्त करने की मांग को लेकर ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही शिक्षक की प्रतिनियुक्ति रद्द कर उन्हें विद्यालय में पुन: नियमित अध्यापन के लिए नहीं भेजा गया, तो इससे कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा।

एकमात्र शिक्षक के हटने से पढ़ाई ठप होने की नौबत

ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेटा, जो जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर ग्रामीण अंचल में स्थित है, जिसमें वर्तमान में अंग्रेजी विषय के केवल एक ही शिक्षक कार्यरत हैं। विद्यालय में द्वितीय श्रेणी अध्यापक का पद पहले से ही रिक्त चल रहा है। ऐसे में एकमात्र शिक्षक को तहसील कार्यालय में प्रतिनियुक्त कर दिए जाने से विद्यालय में अंग्रेजी शिक्षण व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा मिलना उनका मौलिक अधिकार है। इकलौते शिक्षक की प्रतिनियुक्ति से 300 बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

अन्य कार्मिक की ड्यूटी लगाने की मांग

समाजसेवी अनिल जैन, जिला परिषद सदस्य जयचंद आमलिया व ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि शादाब हुसैन की तहसील कार्यालय में लगाई गई प्रतिनियुक्ति तुरंत प्रभाव से निरस्त की जाए और उनके स्थान पर किसी अन्य विभाग या विद्यालय के गैर-शिक्षण कार्मिक की ड्यूटी लगाई जाए। इससे विद्यालय में विद्यार्थियों का अध्ययन बिना किसी रुकावट के सुचारू रह सकेगा।

ज्ञापन सौंपने के दौरान जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों की इस न्यायसंगत मांग का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है, जिस पर तुरंत सकारात्मक निर्णय लिया जाना चाहिए।

इस अवसर पर समाजसेवी अनिल जैन, जिला परिषद सदस्य जयचंद आमलिया, ग्राम पंचायत रेटा प्रशासक अमृत देवी, कानजी भाई, आनंद, हरीश कोटेड, गौतमलाल आमलिया सहित समस्त ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

ई-20 पेट्रोल के खिलाफ केजरीवाल का पीएम आवास तक मार्च

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज पीएम आवास तक मार्च करेंगे। केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह घोषणा की थी कि वे 4 अगस्त को दोपहर 12 बजे पीएम आवास तक जाएंगे। दिल्ली के पूर्व सीएम यह प्रदर्शन ई-20 पेट्रोल के खिलाफ कर रहे हैं। इस दौरान वे अपने साथ 100 लोगों को लेकर जाएंगे और जनहित याचिकाएं सौंपेंगे। केजरीवाल का आरोप है कि भारत ने अमेरिका से इथेनॉल खरीदने के लिए ट्रम्प के सामने घुटने टेक दिए हैं। सरकार दबाव में आकर ई-20 फ्यूल को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने दावा किया कि सरकार का ई-20 पर लगातार जोर देना किसी छिपे हुए एजेंडे की ओर इशारा करता है। लोग की गाड़ियों में कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने कहा है कि केजरीवाल को मार्च की इजाजत नहीं दी जाएगी। और किसी भी जुलूस को रोकने के लिए सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं।

पीएम को सौंपेंगे 2 लाख लोगों के हस्ताक्षर

केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने पिछले महीने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा था। जिसमें ई-20 पेट्रोल से जुड़ी चिंताओं पर चर्चा के लिए समय मांगा था। केजरीवाल का दावा है कि उन्हें इस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए अब वे खुद पीएम आवास जाकर जनता की साइन की हुई याचिकाएं सौंपेंगे। आम आदमी पार्टी संयोजन ने यह मांग भी रखी है कि पेट्रोल पंपों पर शुद्ध पेट्रोल और ई-20 दोनों के ऑप्शन मिलने चाहिए। ई-20 पेट्रोल की कीमतों में कटौती की जाए।

बीजेपी बोली- केजरीवाल अराजकता की राजनीति कर रहे

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने केजरीवाल के मार्च के ऐलान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस और केजरीवाल के बीच देश का नंबर 1 अराजकतावादी बनने की होड़ का हिस्सा है। मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि जब से कांग्रेस ने पीएम आवास पर प्रदर्शन किया है, केजरीवाल खुद को पीछे महसूस कर रहे हैं। बिना परमिशन धरना-प्रदर्शन करना और फिर विक्टिम कार्ड खेलना केजरीवाल की पुरानी राजनीतिक शैली है। उन्होंने दावा किया कि जब पुलिस उन्हें बिना अनुमति के पीएम आवास में घुसने से रोकेगी, तो केजरीवाल फिर से यही कहेंगे कि सरकार ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया।

कश्मीर में टारगेट किलिंग रोकने की तैयारी

श्रीनगर। कश्मीर के कुलगाम में 4 दिन पहले दो बाहरी मजदूरों की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने नई सुरक्षा रणनीति पर चर्चा तेज कर दी है। कश्मीर घाटी में इस वक्त करीब 4 लाख प्रवासी मजदूर रहते हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने इनकी सुरक्षा को लेकर अहम बैठक की है। इसमें कुछ निर्देश तय हुए हैं। प्रशासन से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इन निर्देशों में दो बातें सबसे अहम हैं। **पहली**- घाटी में जहां प्रवासी मजदूर बिखरे हैं, असुरक्षित जगहों पर रह रहे हैं।

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पुनाली की बैठक आयोजित, पंचायतीराज चुनाव में जीत का लिया संकल्प

गांव-गांव जाकर कांग्रेस की विचारधारा पहुंचाने का कार्यकर्ताओं से किया आह्वान

संतोष व्यास@जस्टिस एम्बिट

डूंगरपुर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पुनाली की एक महत्वपूर्ण बैठक ब्लॉक अध्यक्ष व आसपुर विधानसभा प्रत्याशी राकेश रोत की अध्यक्षता में मंगलवार को दोवडा में आयोजित की गई। बैठक में आगामी पंचायती राज चुनावों को लेकर रणनीति बनाने के साथ ही पार्टी की जीत का संकल्प लिया गया। बैठक में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व विधायक गणेश घोघरा, विधानसभा प्रभारी नरेंद्र खोड़निया, पूर्व उप जिलाप्रमुख प्रेमकुमार पाटीदार, पंचायती राज प्रभारी मनोज पाटीदार सहित कई वरिष्ठ नेताओं, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का आह्वान

बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और आगामी पंचायती राज चुनावों में पार्टी की विजय सुनिश्चित करने पर जोर दिया। नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सदैव किसानों, मजदूरों, युवाओं और महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी जनता की आवाज को मजबूती से उठाती रहेगी।

भाजपा सरकार पर बोला तीखा हमला

बैठक के दौरान भाजपा सरकार की नीतियों पर चर्चा करते हुए वक्ताओं ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच रहा है। युवाओं के रोजगार की समस्या और ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की गई।

गांव-गांव तक पहुंचेगी कांग्रेस की विचारधारा

नेताओं ने स्पष्ट किया कि जनता अब झूठे वादों के बहकावे में आने वाली नहीं है और आगामी चुनावों में विकास व जवाबदेही के आधार पर ही निर्णय करेगी। इस दौरान कार्यकर्ताओं से गांव-गांव और ढाणी-ढाणी जाकर कांग्रेस की जनहितैषी नीतियों और विचारधारा को पहुंचाने की अपील की गई। बैठक के अंत में उपस्थित सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस का परचम लहराने का सामूहिक संकल्प लिया।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर प्रदर्शन

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के 12वें दिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही महज 3 मिनट चलने के बाद दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही करीब आधे घंटे हंगामे के बाद 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच बहस हुई। खड़गे ने कहा- राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया था। ट्रस्ट को 70 एकड़ से ज्यादा जमीन सौंपी। पीएम खुद राम मंदिर से जुड़े हर आयोजन में शामिल हुए। अब ED, CBI और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियां कहां हैं।सरकार को सदन में इसका जवाब देना चाहिए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा- कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सालों तक भगवान राम और राम मंदिर का विरोध करती रही हैं। राम मंदिर बनने पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया था। आज वही लोग घड़ियाली आंसू बहाकर देश को गुमराह नहीं कर सकते। पहले भगवान राम का अपमान करने के लिए देश से माफी मांगिए, उसके बाद सरकार से जवाब मांगिए।

प्रियंका बोलीं- बीजेपी से जनता ऊब चुकी है, उपचुनाव नतीजे इसकी शुरुआत

बिहार और मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की हार पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि अब साफ है कि जनता भाजपा से ऊब चुकी है। लोग समझ रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि यह सिर्फ शुरुआत है।

खड़गे बोले- सरकार चंदा चोरी पर जवाब दे, रिजिजू ने कहा- विपक्ष घड़ियाली आंसू बहा रहा

राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर कैश, चढ़ावा, गहने और जमीन से जुड़े गंभीर आरोप सामने आए हैं। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया था। संसद में इसकी घोषणा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। खड़गे ने कहा- पीएम ने ट्रस्ट को 70 एकड़ से ज्यादा जमीन सौंपी और वे राम मंदिर के हर महत्वपूर्ण आयोजन में शामिल होते रहे हैं। खड़गे ने सवाल किया कि **ED, CBI** और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियां इस मामले में क्या कर रही हैं। सरकार को सदन में इसका जवाब देना चाहिए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कहा- कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सालों तक भगवान राम और राम मंदिर का विरोध करती रही हैं। राम मंदिर बनने पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया था। आज वही लोग चंदा चोरी का नाटक कर रहे हैं। रिजिजू ने कहा- राम विरोधी लोग घड़ियाली आंसू बहाकर देश को गुमराह नहीं कर सकते। पहले भगवान राम का अपमान करने के लिए देश से माफी मांगिए, उसके बाद सरकार से जवाब मांगिए।

हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले पर विपक्ष की नारेबाजी और हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार से जवाब और चर्चा की मांग कर रहा है।

श्रीनाथजी की पावन धरा पर 9 अगस्त को होगा कवि देवीलाल जोशी के काव्य-संग्रह 'शुभम-सौंदर्य' का भव्य विमोचन

सत्यम, शिवम, सुन्दरम के दर्शन और शुभम् छन्द से सजी कविताएँ समाज, राष्ट्र व अध्यात्म को देंगी नई दिशा

संतोष व्यास@जस्टिस एम्बिट

डूंगरपुर। वागड़ अंचल के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद्, साहित्यकार एवं सांस्कृतिक चिंतक कवि देवीलाल जोशी के नवीनतम एवं बहुचर्चित काव्य-संग्रह शुभम-सौंदर्य का भव्य विमोचन आगामी 09 अगस्त को पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ, प्रभु श्रीनाथजी की पावन नगरी नाथद्वारा (राजसमंद) में आयोजित होने जा रहा है। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा चयनित इस विशिष्ट कृति के लोकार्पण समारोह में प्रदेश के कई मूर्धन्य साहित्यकार, शिक्षाविद, सांस्कृतिक चिंतक और प्रबुद्ध नागरिक शिरकत करेंगे। उल्लेखनीय है कि डूंगरपुर जिले के पुनाली गाँव निवासी देवीलाल जोशी लंबे समय से शिक्षा-जगत, साहित्य-सृजन और भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार में समर्पित रहे हैं। वे होराइजन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के निदेशक एवं संचालक हैं। उनकी इस नवीनतम कृति शुभम-सौंदर्य को राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा चयन प्रक्रिया में विशेष पहचान मिली है, जिससे सम्पूर्ण वागड़ अंचल सहित प्रांतीय साहित्यिक हलकों में हर्ष की लहर है।

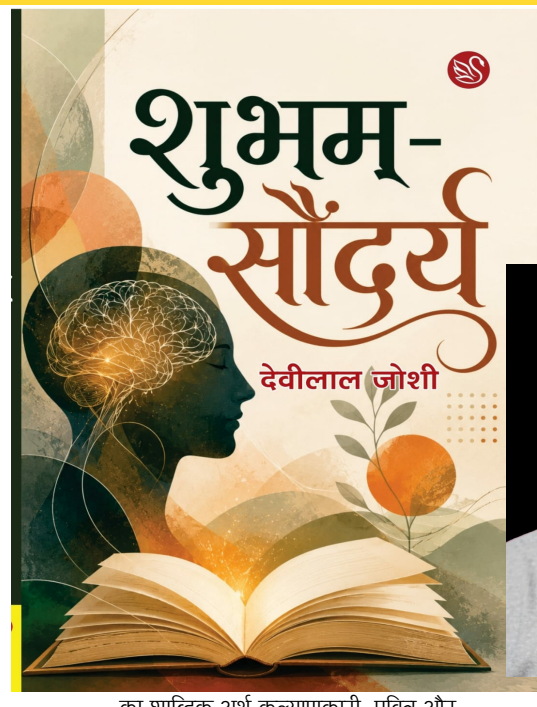

सत्यम, शिवम, सुन्दरम और भारतीय दर्शन की सजीव अभिव्यक्ति

कवि देवीलाल जोशी ने बताया कि शुभम-सौंदर्य का शाब्दिक अर्थ कल्याणकारी, पवित्र और आनंददायक सौंदर्य है। भारतीय दर्शन और कला में सौंदर्य की व्याख्या 'सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम्' के रूप में की गई है, जिसके अनुसार जो सत्य है, वही कल्याणकारी अथवा शुभ है और वही परम सौंदर्य है। जोशी का यह काव्य-संग्रह भी अपनी कविताओं के माध्यम से भारतीय दर्शन के इसी शाश्वत स्वरूप की व्याख्या करता प्रतीत होता है। जोशी ने अपने काव्य-संसार में जीवन के विविध रंगों, मानवीय संबंधों, सामाजिक चेतना, राष्ट्रधर्म, अध्यात्म, प्रेम, प्रकृति, दर्शन, सौंदर्य और संवेदना जैसे व्यापक विषयों को अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि और गहराई के साथ अभिव्यक्त किया है।

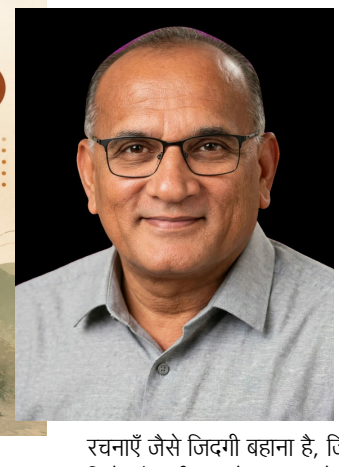

जीवन-दर्शन, आत्ममंथन और यथार्थ

संग्रह में शामिल रचनाएँ जैसे जिदगी बहाना है, जिदगी में ज़िदगी मिले और जीवन को अब समझें में रचनाकार जीवन को केवल घटनाओं का क्रम नहीं मानते, बल्कि उसे आत्मबोध, अनुभूति और निरंतर सीखने की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। इन रचनाओं में जीवन-दर्शन और आत्ममंथन की गहराई के साथ-साथ जीवन के भोगे हुए यथार्थ के दर्शन भी होते हैं।

संत परंपरा, लोकमंगल और राष्ट्रचेतना

भारतीय सांस्कृतिक चेतना और संत परंपरा से कवि का गहरा जुड़ाव लोक मंगल तुलसी, कविवर तुलसीदास, फक्कड़ निर्गुण कबीर पंथ, गुरु-शिष्य आह्वान और गुरु बिन ज्ञान नहीं जैसी रचनाओं में साफ़ तौर पर झलकता है। इनके माध्यम से लेखक ने भारतीय ज्ञान परंपरा, लोकमंगल और गुरु की महिमा को नए संदर्भों में पिरोया है। यहाँ अध्यात्म केवल उपदेश नहीं, बल्कि जीवन को स्पष्ट दिशा देने वाली जाग्रत चेतना बनकर उभरा है। साथ ही, राष्ट्र और भाषा के प्रति उत्तरदायित्व की भावना भी इसमें मुखर हुई है। विश्व पटल-हिंदी महके जैसी रचना में हिंदी संपूर्ण भारत की पहचान, एकता और संस्कृति का मूल आधार बनकर उभरती है।

नाथद्वारा में तैयारियाँ अंतिम चरण में

श्वेतवर्णा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित इस कृति के लोकार्पण समारोह को लेकर नाथद्वारा एवं वागड़ क्षेत्र के साहित्य प्रेमियों में खासा उत्साह है। 9 अगस्त को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में प्रदेशभर के साहित्य अनुरागी प्रभु श्रीनाथजी के दर्शन के साथ-साथ इस साहित्यिक उत्सव के साक्षी बनेंगे।

शुभम् छन्द की मौलिकता और साहित्यिक योगदान

इस संग्रह की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी कविताएँ कवि देवीलाल जोशी की स्वनिर्मित एवं मौलिक अभिव्यक्ति-शैली शुभम् छन्द में रची गई हैं, जो उनकी अद्भुत सृजनात्मक मौलिकता को उजागर करती हैं। लेखन के साथ-साथ जोशी ने श्रीमद्भगवद्गीता पर ज्ञानपरक पुस्तकों का सृजन, स्थानीय इतिहास व स्मारिकाओं का निर्माण तथा लगभग 100 से अधिक लोकगीत, गरबा एवं प्रेरक गीतों की रचना की है। इससे पूर्व उनकी पुस्तक शुभम् भवन्तु शुभम को भी व्यापक जन-सराहना प्राप्त हो चुकी है।

डेगाना में एक दिन में एक लाख पौधारोपण का ऐतिहासिक अभियान सफल, जनभागीदारी से हरित भविष्य की मजबूत नींव

@जस्टिस एम्बिट

नागौर। पर्यावरण संरक्षण एवं %हरियालो राजस्थान अभियान के संकल्प को साकार करने की दिशा में 4 अगस्त 2026 को नागौर के डेगाना की पंचायत समिति बैरून्दा में एक दिन में एक लाख पौधारोपण का ऐतिहासिक लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया। पंचायत समिति क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायत को चार हजार पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया था, जिसे ग्राम पंचायतों के सामूहिक प्रयास और जनसहभागिता से निर्धारित समय में पूर्ण कर लिया गया। यह अभियान क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजागरूकता और सामूहिक जिम्मेदारी का प्रेरणादायक उदाहरण बनकर सामने आया। कार्यक्रम का मुख्य आयोजन नवगठित ग्राम पंचायत सुरपुरा, ग्राम पंचायत निबोला बिसियां तथा पिरामिड वैली स्थित तेजाजी हर्सौर परिसर में आयोजित किया गया। इन स्थानों पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों तथा ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक पौधारोपण किया और अधिक से अधिक लोगों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने का संदेश दिया। सभी प्रतिभागियों ने पौधारोपण के साथ-साथ लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल और संरक्षण का भी सामूहिक संकल्प लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डेगाना विधायक अजय सिंह किलक ने कहा कि पौधारोपण केवल एक अभियान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पौधे लगाने के साथ उनका संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में पौधों की देखरेख के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं विकसित करने, जल उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा दीर्घकालिक संरक्षण की दिशा में प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए नागौर जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने कहा कि यह अभियान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जनसहभागिता का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक यदि पौधारोपण के साथ उसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी निभाए, तो हरित एवं स्वच्छ भविष्य का सपना साकार किया जा सकता है। उन्होंने सभी से पौधों की नियमित देखभाल करने और उन्हें वृक्ष बनने तक संरक्षित रखने का आह्वान किया।

इस अवसर पर बड़ी संख्या में जन्म प्रतिनिधि, प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी, समाज सेवि संस्थाओं के प्रतिनिधि, विद्यालयों के छात्र-छात्राएं व ग्रामवासी उपस्थित रहे ।

राउमावि छैला खेरवाड़ा में विधायक गणेश घोघरा का औचक निरीक्षण; एक थाली में खाना खाने को मजबूर मासूम, व्यवस्थाओं में भारी धांधली उजागर

शिक्षकों की लेटलतीफी, पोषाहार में फर्जीवाड़ा और जर्जर भवन का सच आया सामने; मनमानी करने वाले शिक्षक पर विभागीय कार्रवाई के निर्देश

संतोष व्यास@जस्टिस एम्बिट

डूंगरपुर। जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छैला खेरवाड़ा में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली और मूलभूत सुविधाओं की बदतर स्थिति उजागर हुई है। शिक्षकों की कमी और मध्याह्न भोजन वितरण में गंभीर अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर डूंगरपुर विधायक गणेश घोघरा ने मंगलवार को विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिली व्यापक खामियों और अव्यवस्थाओं को देखकर विधायक ने गहरी नाराजगी और चिंता व्यक्त की।

एक ही थाली में 3-4 बच्चे खाने को मजबूर, पढ़ाई में भारी लापरवाही

निरीक्षण के दौरान स्कूल की जो तस्वीर सामने आई, वह बेहद चिंताजनक थी। मध्याह्न भोजन वितरण में भारी फर्जीवाड़ा पाया गया, जहां बच्चों को पर्याप्त पोषण देने के बजाय एक ही थाली में तीन से चार बच्चों को खाना खाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। शिक्षा के स्तर की जांच के लिए जब शिक्षक डायरी और छात्रों की कॉपियों का मिलान किया गया, तो उसमें भारी अंतर पाया गया, जिससे अध्यापन कार्य में बरती जा रही गंभीर लापरवाही स्पष्ट उजागर हुई। इसके अलावा कई शिक्षकों की समय पर न आने की पोल भी खुली।

जर्जर भवन से हादसे का खतरा, अभिभावक टीसी कटवाने को मजबूर

विद्यालय परिसर की स्थिति भी अत्यंत दयनीय पाई गई। कई कमरे पूरी तरह जर्जर और खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, जिससे हर समय किसी बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है। विधायक ने कहा कि स्कूल की इन बदहाल स्थितियों और राजनीति का अखाड़ा बन चुके माहौल से तंग आकर अभिभावक अपने बच्चों की टीसी कटवाने को मजबूर हो रहे हैं। विधायक गणेश घोघरा ने मौके से ही विभागीय उच्च अधिकारियों को पूरी स्थिति से अवगत कराया और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त से सख्त प्रशासनिक कदम उठाने की मांग की। उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी कार्मिक को बख्शा नहीं जाएगा।

दबाव और धौंस जमाने वाले शिक्षक पर गाज, उदयपुर डेपुटेशन का मामला भी उछला

विद्यालय के माहौल को लेकर भी गंभीर शिकायतें सामने आई। स्टाफ सदस्यों ने शिक्षक धनेश्वर हड़ात पर स्कूल का माहौल खराब करने, अन्य शिक्षकों व कार्यवाहक प्रधानाचार्य को डराने-धमकाने और धौंस जमाने का आरोप लगाया। विधायक घोघरा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को मौके पर बुलाया और शिक्षक के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निरीक्षण में यह बात भी सामने आई कि स्कूल की एक शिक्षिका की प्रतिनियुक्ति लंबे समय से उदयपुर में है, लेकिन उनका पद और वेतन इसी स्कूल से जारी हो रहा है। इसके चलते यहां एक सीट खाली पड़ी है और स्थानीय विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।